भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3707

उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024 (बुधवार)

27 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

3707. श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वीकृत की गई अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये किस प्रकार की परियोजनाएं हैं और उनका उद्देश्य किस प्रकार क्षेत्र में संपर्क और विकास में सुधार लाना है; और

(ख) सरकार का किस प्रकार अगले कुछ वर्षों के दौरान 3,417 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 अवसंरचना परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृत करके विभिन्न स्कीमों अर्थात उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) स्कीम, विशेष विकास पैकेजों और एनईसी की स्कीमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करता है।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना के विकास और बेहतर सड़क, रेल, जल, दूरसंचार और हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, रेल लाइनों का ब्रॉड गेज रूपांतरण तथा राजधानी कनेक्टिविटी रेल परियोजनाएं, व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्कीमें आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी स्कीमों/परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी सकल बजटीय सहायता का 10% व्यय करने का अधिदेश है।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पिछले 03 वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) के तहत 3,417.68 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एनईएसआईडीएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का निष्पादन पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भी विभिन्न स्तरों पर एनईएसआईडीएस के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की गहनता से निगरानी करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों, जिनमें अन्य के साथ-साथ एनईएसआईडीएस भी शामिल है, के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के नियमित निरीक्षण और मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालय द्वारा सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड स्तरीय तकनीकी सहायता इकाइयां (एफटीएसयू) स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में परियोजना गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (पीक्यूएम/टीपीटीआई) एजेंसियों को नियुक्त किया गया है।

*****